छत्तीसगढ़ के न्यायिक अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक और कदम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बिलासपुर: छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा के नेतृत्व में प्रदेश में न्यायिक अधोसंरचना को अत्याधुनिक और पक्षकारों के लिए सुविधाजनक बनाने के प्रयासों को लगातार गति मिल रही है। इसी क्रम में शुक्रवार 1 अगस्त 2025 को जिला न्यायालय महासमुंद में 2 करोड़ 33 लाख 72 हजार 680 रुपए की लागत से नवनिर्मित दो मंजिला एडीआर (वैकल्पिक विवाद समाधान) भवन का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम में न्यायमूर्ति संजय के. अग्रवाल, कार्यपालक अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं न्यायमूर्ति दीपक कुमार तिवारी, पोर्टफोलियो न्यायाधीश, जिला महासमुंद उपस्थिति रहे।

वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करते मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा • हाई कोर्ट

प्रकृति की गोद में न्याय व्यवस्था को सशक्त बनाने का संकल्प

मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य की सराहना करते हुए कहा कि, आज सुबह जब मैं अखबार पढ़ रहा था तो एक जलप्रपात की सुंदर तस्वीर देखी, जो हरियाली के बीच बह रहा था। यह देखकर मुझे यह महसूस हुआ कि छत्तीसगढ़ प्रकृति की गोद में बसा है। हमारा दायित्व है कि हम न्याय व्यवस्था की बेहतरी के लिए मिलकर कार्य करें ताकि यहां के लोगों को शीघ्र, सरल और सुविधायुक्त न्याय मिल सके। यह भवन विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान का एक सशक्त माध्यम सिद्ध होगा और महासमुंद जिला इस अभियान में एक सफल उदाहरण प्रस्तुत करेगा।